

II/लॉगो/स्ट्रीट/2017/4421

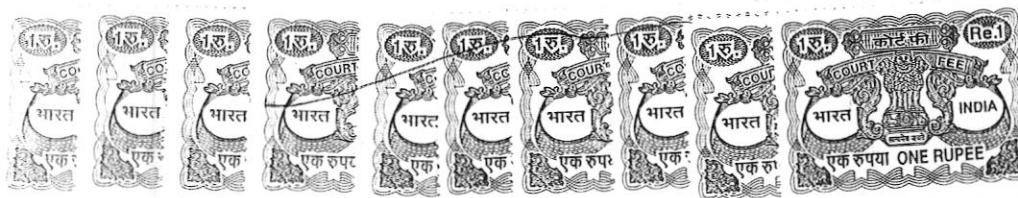
45

यायालय श्री मान् सदस्य पहोचय राजस्व पण्डल ग्वालियर

सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवा प०प्र०



निगरनी प्रकरण क्रमांक



Rs. 30/-

श्यामलाल कुम्हार तनब श्री छविलाल कुम्हार उम्र 63 साल

निवासी ग्राम कुबरी, तहसील चुरहट जिला सीधी प०प्र०

----- आवेदक /निगराकार

विरुद्ध

1- प०प्र० शासन

2- नद्याक्रांती सिंहपिताश्री अयोध्या सिंह चौहान, निवासी हाल

मुकाम कुबरी तहसील चुरहट जिला सीधी प०प्र०

----- अनावेदकगण/ गैरनिगराकारगण

निगराजी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर

आयुक्त पहोचय रीवा संभाग रीवा मे द्वितीय

अपील प्रकरण क्रमांक 01/ अपील/16-17मे

पारित आदेश दिनांक 30-8-17 जिसके

डारा आवेदक/निगराकार की अपील निरस्त करदी
गई।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 प०प्र० मूराजस्व

संहितासन 1959हि०

B

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग—अ

प्रकरण क्रमांक दो—निगरानी/सीधी/भू.रा./2017/4421

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
०७-०३-२०१८	<p>पूर्व पेशी पर आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की प्रचलनशीलता पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक १/२०१६-१७ अपील में पारित आदेश दिनांक ३०-८-१७ के विरुद्ध म०प्र०भू राजस्व संहिता १९५९ की धारा ५० के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्कों पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक १/२०१६-१७ अपील में पारित आदेश दिनांक ३०-८-१७ से अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आदेश दिनांक ९-३-१७ में लिये गये निर्णय एंव तहसीलदार चुरहट के आदेश दिनांक २८-५-१७ में शासकीय भूमि पर आवेदक को अतिक्रमणकर्ता मानकर दिये गये आदेश को पुष्टिकृत किया है। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक ३०-८-१७ अनुसार तहसीलदार चुरहट व्दारा प्रकरण क्रमांक १८ अ ६ अ/१०-११ में पारित आदेश दिनांक २८-५-१७ में अंकित अनुसार भूमि शासकीय है किन्तु आवेदक की ओर से अपील मेमो में अथवा प्रथक से दस्तावेज प्रस्तुत यह प्रमाणित नहीं किया है कि भूमि किस सर्व क्रमांक की है जिसका कितना रकवा है व किस मौजे की भूमि है एंव १०० वर्ष से जब अपील मेमो में आवेदक भूमि में कब्जा की भूमि होना बता रहा है उसके व्दारा अभिलेख के आधार पर भी इसका पुष्टिकरण नहीं किया है जबकि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के</p>	

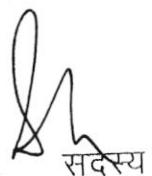
प्रकरण क्रमांक 1/2016-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-8-17 का पद 3 इस प्रकार है :-

“ तहसीलदार चुरहट के प्र०क० 18 अ 6 अ/10-11 पारित आदेश दिनांक 28-5-17 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी ने शासकीय भूमि पर कब्जा दर्ज करना चाहता था, जिससे नायव तहसीलदार द्वारा निरस्त करने पर अपील प्रस्तुत की गई थी, अधीनस्थ न्यायालीय ने आदेशित किया है कि अपीलार्थी का शासकीय भूमि पर कब्जा है जिसका संरक्षण करना अनिवार्य है इसी आधार पर अपील निरस्त की गई है।

चूंकि अपीलार्थी शासकीय भूमि पर अपर कब्जा दर्ज कराना चाहता है जबकि शासकीय भूमियों पर अतिकामकों का कब्जा हटाने के शासन के निर्देश हैं ऐसी स्थिति पर अधीनस्थ न्यायालय ने शासन के निर्देशों के अनुरूप अपीलार्थी का आवेदन पत्र खारिज कर कोई त्रुटि नहीं की है।”

उपरोक्तानुसार विवेचना करते हुये अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 1/2016-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-8-17 से आवेदक की अपील निरस्त की है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 30-8-17 में हस्तक्षेप की गुजारा नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है।


सदस्य